

[1]

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 72/2024  
(जीसीएमएस संख्या 2024/79)

निर्णय दिनांक:- 28-11-25

1. रमेश कुमार पुत्र किशोरीलाल जाति अग्रवाल निवासी वार्ड संख्या 14  
खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजूवाला।

—रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 07-03-2000  
आवंटन अधिकारी, खाजूवाला

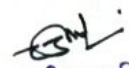


उपस्थिति:-

1. श्री पुरुषोत्तम सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील आवंटन अधिकारी, खाजूवाला के आदेश दिनांक 07-03-2000 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

  
राजस्व अपील अधिकारी  
बीकानेर


3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील खाजूवाला में चक 22 बीडी के मुरब्बा नम्बर 93/05 तादादी 25 बीघा भूमि के बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा तत्पश्चात् अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रकबा अन्तराष्ट्रीय सीमा की 2 किमी की परिधि में है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।



इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब कोई तारीख पेशी नहीं बताई गई थी। अपीलांट आज दिनांक को भी भूमि आवंटन करवाने का पात्र है क्योंकि प्रार्थी का पेशा खेती है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2015 स्प.पेज 443 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

उन्होंने मियाद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियाद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियाद प्रार्थना पत्र में मियाद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा


  
राजस्व अपील अधिकारी  
बीकानेर

चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।
6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते हैं। जहाँ तक मियाद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोजेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुण पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियाद घोषित की जाती है।



प्रकरण में जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट ने आवंटन अधिकारी के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसील खाजूवाला में चक 22 बीडी के मुरब्बा नम्बर 93/05 तादादी 25 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई थी। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट के विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रकबा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की 2 किमी की परिधि में स्थित होने से प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज किया जाता है। इसके विपरीत अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है एवं यदि प्रार्थी द्वारा आवेदित रकबा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक स्थित है तो भी प्रार्थी को अन्य कोई


  
राजस्व अपील अधिकारी  
बीकानेर

रकबे हेतु पात्र घोषित किया जाना था। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

इस संबंध में हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण विशेष आवंटन के जरिये सरकारी कृषि भूमि के विक्रय से संबंधित है। यह स्वीकृत स्थिति है कि जिस भूमि का गजट में प्रकाशन होता है वह भूमि विक्रय के लिए उपलब्ध होती है। अपीलांट द्वारा गजट में प्रकाशित उपलब्ध भूमियों की सूचना के आधार पर प्रश्नगत भूमि के लिए आवेदन किया था। अपीलाधीन आदेश द्वारा यह लिखकर आवेदन खारिज कर दिया गया कि प्रश्नगत भूमि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के 2 किमी की परिधि में होने के कारण आवंटन नहीं किया जा सकता। प्रश्नगत भूमि के आवेदन करने में अपीलांट की कोई गलती नहीं थी। उसके द्वारा गजट में प्रकाशित प्रश्नगत भूमि के लिए आवेदन किया गया था। यदि प्रश्नगत भूमि अपीलांट को आवंटित नहीं की जा सकती थी तो इस सूरत में अपीलांट को गजट में प्रकाशित अन्य भूमि के आवेदन करने हेतु अवसर एवं सूचना दिया जाना आवश्यक था। पत्रावली पर ऐसा कोई नोटिस या अन्य दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे कि यह साबित हो कि प्रश्नगत भूमि के आवंटन खारिज होने एवं अन्य भूमि के आवंटन हेतु आवेदन करने की सूचना विधिवत अपीलांट को दी गई है।



7. अतः उक्त नियम के प्रकाश में अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि संबंधित गजट में यदि अनावेदित तथा अनारक्षित भूमि उपलब्ध हो तो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों व अद्यतन परिपत्रों के आलोक में अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
8. निर्णय आज दिनांक 28-11-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

  
 (उम्मेद सिंह रतनू)  
 राज्य अपील अधिकारी  
 बीकानेर